*न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और न्यायमूर्ति एन. सी. खिची के समक्ष*

**पंजाब पंचायती राज खेड़ परिषद,-अपीलार्थी**

***बनाम***

**जस्मोहन सिंह और अन्य-उत्तरदाता**

***1991* का एल. पी. ए. 763**

**3 दिसंबर, 1998**

*लेटर्स पेटेंट अपील, 1919-Cl.X-विघटित सशस्त्र बल कार्मिक (पंजाब राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1968-नियम 5-वरिष्ठता-सशस्त्र* बलों के *सदस्य* जो *आपातकालीन कमीशन अधिकारी या अल्पकालिक सेवा नियमित कमीशन अधिकारी नहीं हो सकते हैं, वे वरिष्ठता के लाभ के हकदार हैं-नियम 5 कि व्याख्या कि गई।*

*अभिनिर्धारीत किया गया कि* नियम 5 में संशोधित प्रावधान निस्संदेह आपातकालीन कमीशन अधिकारी, अल्पकालिक सेवा कमीशन अधिकारी और उन सभी को संदर्भित करता है जो ''अक्षमता के कारण अमान्य'' हैं।

इस प्रकार, यदि इस तरह से व्याख्या की जाती है, तो एक सैनिक जिसे अक्षमता के कारण अमान्य कर दिया गया है, वह भी नियम 5 के तहत लाभ का हकदार होगा। अन्यथा, उन्हें विचार से बाहर रखने का कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि सैनिकों आदि को नियमों के तहत लाभों से बाहर रखा गया है।

(पैरा 17)

*इसके अलावा*, यदि नियमों के प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाता है, तो सशस्त्र बलों के सदस्य जो आपातकालीन कमीशन अधिकारी या अल्पकालिक सेवा या नियमित कमीशन अधिकारी नहीं हो सकते हैं, उन्हें उस श्रेणी या व्यक्तियों से बाहर नहीं रखा जाता है जो नियम 5 के तहत विचार किए गए वरिष्ठता आदि के लाभ के हकदार हैं। चूंकि रिक्तियों के आरक्षण को विनियमित करने और सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ देने के लिए नियम लागू किए गए थे, इसलिए सशस्त्र बलों से उनकी रिहाई के समय उनके द्वारा रखे गए पद के कारण उन्हें सेवा का लाभ देने से वंचित करना अनुचित होगा।

(पैरा 19)

दीपक अग्निहोत्री, अपीलार्थी के *अधिवक्ता।*

*जवाहर लाल गुप्ता, नयायमूर्ति (मौखिक)*

(1) क्या प्रत्यर्थी पंजाब पंचायती राज खेल परिषद में कुश्ती कोच के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले अपने द्वारा प्रदान की गई सेना सेवा के लाभ का हकदार नहीं था? यह संक्षिप्त प्रश्न है जो इस लेटर्स पेटेंट अपील में विचार के लिए उत्पन्न होता है। कुछ तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है।

(2) उत्तरदाता 11 जुलाई, 1966 को रैंकर के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुआ था। 31 जुलाई, 1975 को उन्हें छुट्टी दे दी गई। 9 जनवरी, 1976 को पंजाब पंचायती राज खेल परिषद (जिसे इसके बाद अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने प्रशिक्षकों के पदों का विज्ञापन किया। 20% इनमें से कई पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे। उत्तरदाताओ ने पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित *रिक्तियों* में से एक के खिलाफ विचार किए जाने के लिए आवेदन किया। उनका चयन किया गया। 29 जुलाई, 1976 के आदेश के अनुसार, उत्तरदाता को कुश्ती कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। वे वास्तव में 4 अगस्त, 1976 को सेवरम्भ हुए थे।

(3) सेवा में शामिल होने के बाद, उत्तरदाता ने जुलाई 1966 से जुलाई 1975 की अवधि के दौरान अपने द्वारा प्रदान की गई सैन्य सेवा के लाभ के अनुदान के *लिए* दावा किया। 28, 19 अप्रैल के आदेश के माध्यम से, जिसकी प्रति अनुलग्नक पी. 1/ए के रूप में रिकॉर्ड पर रखी गई है, अपीलार्थी ने उत्तरदाता के दावे को स्वीकार कर लिया। उन्हें 16 मई, 1970 से नियुक्त किया हुआ माना गया था। उनकी वरिष्ठता और वेतन तदनुसार तय किए गए थे।

(4) जब वह कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे थे, तब उत्तरदाता ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना में एक पद के लिए आवेदन किया। आवेदन उचित माध्यम से भेजा *गया* था। उन्हें 17 फरवरी, 1989 के आदेश के अनुसार चुना गया था, उन्हें उसी दिन नियुक्ति दी गई थी। यह प्रावधान किया गया था कि उनके द्वारा पहले से रखे गए पद पर उनके वेतन की रक्षा की जाएगी। नियुक्ति पत्र मिलने पर उत्तरदाता ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद, 4 अप्रैल, 1989 को उत्तरदाता को सूचित किया गया कि वह ''उक्त लाभ का हकदार नहीं है'' क्योंकि वह सैन्य सेवा के लाभ के अनुदान को नियंत्रित करने वाले नियमों के नियम 5 (1) में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है। उन्हें यह समझाने के लिए कहा गया कि लाभ क्यों नहीं वापस लिया जाए। उत्तरदाता ने नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। इससे पहले कि कोई आदेश पारित किया जा सके, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। ऐसा प्रतीत होता है कि-11 अक्टूबर, 1989 के आदेश के माध्यम से, सरकार ने प्रतिवादी को दिए गए लाभ को वापस लेने का निर्णय लिया। इस आदेश की एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक पी.11 है।

(5) विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले पर विचार करने के बाद कहा कि "प्रशिक्षकों के पद के लिए विज्ञापन 9 जनवरी, 1976 को जारी किया गया था और साक्षात्कार भी 23 अप्रैल, 1976 को आयोजित किया गया था। यद्यपि नियुक्ति पत्र बाद में जारी किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता के मामले में संशोधित नियम लागू नहीं किया जा सका। याचिकाकर्ता के वकील का तर्क था कि चूंकि जो रिक्ति दाखिल करने (भरने) की मांग की गई थी, वह 1968 के नियमों के संशोधन से पहले हुई थी और वास्तव में रिक्तियों को भरने की

प्रक्रिया 1968 के नियमों के संशोधन से पहले शुरू हो गई थी, इसलिए संशोधन याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं किया जा सका और उसका मामला 1968 के नियमों के नियम 5 के अंतर्गत आता था, जैसा कि 3 मई, 1976 से पहले था।'' विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया कि कर्मचारी को लाभ उचित रूप से दिया गया था। नतीजतन, 11 अक्टूबर, 1989 का आदेश, जिसकी एक प्रति अनुबंध पी. 11 के रूप में रिकॉर्ड में पेश की गई है, रद्द कर दिया गया।

(6) विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से व्यथित, खेड परिषद ने वर्तमान लेटर्स पेटेंट अपील दायर की है।

(7) श्री अग्निहोत्री ने तर्क दिया है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि प्रतिवादी 3 मई, 1976 की अधिसूचना के अनुसार *संशोधित* नियम 5 के प्रावधानों द्वारा शासित नहीं था। इसके अलावा, यह तर्क दिया गया है कि सैन्य सेवा का लाभ प्रत्यर्थी को स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वह न तो एक कमीशन अधिकारी था और न ही एक अल्प-सेवा कमीशन अधिकारी। इसके अलावा, सैन्य सेवा के कारण या उससे बढ़ी हुई अक्षमता के कारण उन्हें अमान्य नहीं किया गया था। नतीजतन उनका मामला नियम 5 के प्रावधानों के दायरे में नहीं आया।

(8) उत्तरदाता के पक्ष में कोई भी मामला लड़ने के लिए पेश नहीं हुआ है।

(9) पंजाब सरकार ने विघटित सशस्त्र बल कार्मिक (पंजाब राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1968 जारी किए थे। इन नियमों को ''भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के विघटित आपातकालीन कमीशन अधिकारियों, अल्पकालिक सेवा नियमित कमीशन अधिकारियों, कनिष्ठ कमीशन अधिकारियों, गैर-कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंकों के लिए बनाया गया था'' फिर भी आगे, नियम 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 20% गैर-तकनीकी पद होंगे जो रिहा भारतीय सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने 1 नवंबर, 1962 के दिन भर्ती हुए या उसके बाद कभी भी भारतीय सशस्त्र बल से रिहा हुए। अभिव्यक्ति ''भारतीय सशस्त्र बलों से रिहा किया गयाके लिए पंजाब राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण को विनियमित करने'' के लिए जारी किया गया था। अभिव्यक्ति ''भारतीय सशस्त्र बलों को रिहा किया गया कार्मिक'' उन व्यक्तियों को बाहर नहीं करता है जो नियुक्त नहीं हैं या रैंक से संबंधित नहीं हैं। नियम 5 जैसा कि यह शुरू में था, निम्नानुसार प्रदान किया गया है:—

> ''5 (1) नियम 3 के तहत आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता और वेतन का निर्धारण इस धारणा पर किया जाएगा कि वे आयोग से पहले सैन्य सेवा या प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद पहले अवसर पर राज्य सरकार के तहत सेवा या पद पर शामिल हुए थे।
>
> (2) नियम *3* के तहत आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त और किसी विशेष वर्ष के लिए आवंटित उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी जन्म तिथियों के आधार पर किया जाएगा; आयु में अधिक आयु वाले उम्मीदवार को कम आयु वाले उम्मीदवार से वरिष्ठ रखा जाएगाः
>
> बशर्ते कि एक ही जन्म तिथि वाले उम्मीदवारों के मामले में, वरिष्ठता का निर्धारण परीक्षा या परीक्षा के परिणाम के आधार पर भर्ती प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के अनुसार किया जाएगा।
>
> (3) नियम 3 के तहत आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त सभी उम्मीदवार को, वर्ष में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त उम्मीदवारों से रैंक मे नीचे रखा जाएगा।''

10. ) 7 मई, 1976 कि अधिसूचना के माध्यम से नियम में संशोधन किया गया। यह निम्नानुसार प्रदान करता हैः—

11.इन नियमों को विघटित सशस्त्र बल कार्मिक (पंजाब राज्य गैर-तकनीकी सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण) (पहला संशोधन) नियम, 1976 कहा जा सकता है।

2. इन्हें 1 नवंबर, 1966 से प्रभावी माना जाएगा।

3. विघटित सशस्त्र बल कार्मिक (पंजाब राज्य गैर-तकनीकी सेवा में रिक्तियों का आरक्षण), नियम 1968 के नियम 5 में, उप-नियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

(1) नियम 3 के तहत आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता और वेतन और जो -

(i) आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में, उन्हें चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार जारी किया जाता है; या

(ii)अल्पकालिक सेवा आयोगित अधिकारियों के मामले में, हैं। उनकी सेवा की अवधि समाप्त होने पर जारी किया गया; या

(iii) सैन्य सेवा के कारण होने वाली या बढ़ी हुई अक्षमता के कारण अमान्य हैं;

इस धारणा पर निर्धारित किया जाएगा कि वे आयोग से पहले सैन्य सेवा या प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद पहले अवसर पर राज्य सरकार के तहत सेवा या पद पर शामिल हुए थे।''

(11) इस प्रकार, 7 मई, 1976 को संशोधित नियम को क़ानून की पुस्तक में लाया गया। इसके अलावा, खंड (2) को देखते हुए, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, संशोधित नियमों को 1 नवंबर, 1966 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया था। परिणाम यह है कि संशोधित प्रावधान को 1 नवंबर, 1966 से लागू हुआ माना जाएगा।

(12) यह उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की यथार्थता पर विचार किया जाना चाहिए। यह स्वीकृत स्थिति है कि पदों का विज्ञापन जनवरी, 1976 में किया गया था। केवल पदों का विज्ञापन या साक्षात्कार में उपस्थिति किसी भी उम्मीदवार को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है। चयन की प्रक्रिया की गणना केवल उपयुक्त व्यक्तियों को खोजने के लिए की जाती है। 19 जुलाई, 1976 को जब चयन को अंतिम रूप दिया गया तो प्रक्रिया स्पष्ट हो गई। इसके बाद 29 जुलाई, 1976 को प्रत्यर्थी को प्रस्ताव दिया गया। यह उस तारीख को लागू नियम है जो पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करेगा। वास्तव में, प्रतिवादी 4 अगस्त, 1976 को शामिल हुआ था। उसी दिन से वरिष्ठता के निर्धारण का सवाल उठ सकता था। उस समय नियम का संशोधित प्रावधान स्वीकार्य रूप से लागू था। हमें यह विचार रखने का कोई आधार नहीं मिलता है कि विज्ञापन की तारीख या साक्षात्कार की तारीख पर मौजूद नियम उस व्यक्ति की वरिष्ठता निर्धारित करेगा जिसे इस पद पर चुना और नियुक्त किया गया है। सबसे पहले, यह सेवा में शामिल होने के समय लागू कानून है जो कर्मचारी की स्थिति निर्धारित करेगा। दूसरा, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, संशोधित प्रावधान 1 नवंबर, 1966 से लागू किए गए थे। इसलिए, कानून की कल्पना से, संशोधित प्रावधान पंजाब राज्य के अस्तित्व में आने की तारीख से लागू माने जाएंगे। राज्य का प्रत्येक कर्मचारी

इस प्रावधान द्वारा शासित होगा। उत्तरदाता जो 4 अगस्त, 1976 को सेवा में शामिल हुआ था, वह संशोधित प्रावधान से छूट का दावा नहीं कर सका।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को बनाए रखने में असमर्थ हैं।

(14) सवाल जो अभी भी बना हुआ है वह यह है कि क्या उत्तरदाता सैन्य सेवा के लाभ का हकदार था?

(15) माना जाता है कि, "भारतीय सेना के सशस्त्र बलों के विघटित आपातकालीन कमीशन अधिकारियों और अन्य रैंकों के लिए रिक्तियों के आरक्षण को विनियमित करने के लिए नियम जारी किए गए हैं।" इस प्रकार, इस नियम का सर्वोपरि उद्देश्य सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए आरक्षण प्रदान करना था। नियम 3 के तहत बीस प्रतिशत पद आरक्षित थे। नियम 5 के तहत, जैसा कि यह मूल रूप से था, यह प्रावधान किया गया था कि नियम 3 के तहत आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता और वेतन का निर्धारण इस धारणा पर किया जाएगा कि वे आयोग से पहले सैन्य सेवा या प्रशिक्षण में शामिल होने के बाद पहले अवसर पर राज्य सरकार के तहत सेवा या पद पर शामिल हुए थे। इस नियम में कानूनी कल्पना की शुरुआत करके वरिष्ठता और वेतन प्रदान करने का प्रावधान किया गया था कि व्यक्ति को उस दिन नियुक्त किया गया माना जाएगा जिस दिन उसे प्रतिस्पर्धा करने का पहला अवसर मिला था। यह लाभ सशस्त्र बलों के उन सभी सदस्यों के लिए स्वीकार्य था जिन्हें नियमों की प्रस्तावना में दिए गए विवरण का उत्तर देना था।

(16) सवाल यह उठता है कि क्या संशोधित प्रावधान ने अधिकार छीन लिया? यदि हां, तो इसका क्या तर्क हो सकता है?

(17) नियम 5 में संशोधित प्रावधान निस्संदेह आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक सेवा वाले कमीशन प्राप्त अधिकारियों और उन सभी को संदर्भित करता है जो "अक्षमता के कारण अमान्य" हैं, इस प्रकार, यदि इस तरह से व्याख्या की जाती है, तो एक सैनिक भी जो विकलांगता के कारण अमान्य हो गया है, नियम 5 के तहत लाभ का हकदार होगा। अन्यथा, उन्हें विचार से बाहर रखने का कोई तर्क प्रतीत नहीं होता है। अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि सैनिकों आदि को नियमों के तहत लाभों से बाहर रखा गया है।

(18) श्री अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी ने नियम की वैधता को चुनौती नहीं दी थी।ऐसा होने पर, संशोधित प्रावधान को लागू करना होगा जैसा कि यह मौजूद है।

(19) यह तर्क सही नहीं है। याचिका के अवलोकन से पता चलता है कि संशोधित प्रावधानों को चुनौती दी गई है। हालाँकि, हम महसूस करते हैं कि यदि नियमों के प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाता है, तो नियम 5 के तहत सशस्त्र बलों के सदस्य जो आपातकालीन कमीशन अधिकारी या अल्पकालिक सेवा या नियमित कमीशन अधिकारी नहीं हो सकते हैं, उन्हें उन व्यक्तियों की श्रेणी से बाहर नहीं किया जाता है जो वरिष्ठता आदि के लाभ के हकदार हैं। चूंकि रिक्तियों के आरक्षण को विनियमित करने और सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ देने के लिए नियम लागू किए गए थे, इसलिए सशस्त्र बलों से उनकी रिहाई के समय उनके द्वारा रखे गए पद के कारण उन्हें सेवा का लाभ देने से वंचित करना अनुचित होगा।

(20) यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि एक सैनिक और एक आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारी उसी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सैनिक योग्यता सूची में उच्च पद प्राप्त कर सकता है। नियम 5 के खंड (2) के अनुसार, नियम 3 के तहत आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त किए गए और किसी

विशेष वर्ष के लिए आवंटित किए गए सभी उम्मीदवारों की अंतर वरिष्ठता उनकी जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए। इस प्रकार, एक सैनिक जो योग्यता के क्रम में नंबर 1 पर हो सकता है और जो आपातकालीन कमीशन अधिकारी से पहले पैदा हुआ हो सकता है, वह वरिष्ठ माना जाएगा। तथापि, अपीलार्थी द्वारा नियमों पर दी गई व्याख्या के अनुसार, केवल अधिकारी ही वरिष्ठता के उद्देश्य से सैन्य सेवा के लाभ का हकदार हो सकता है। यदि इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया जाता है, तो अधिकारी वरिष्ठ हो जाएगा। परिणाम खंड (2) के तहत विचार किए गए परिणाम के विपरीत होगा। इस प्रकार, अपीलार्थी द्वारा नियमों पर दी गई व्याख्या एक विरोधाभासी परिणाम की ओर ले जाएगी।

(21) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि प्रतिवादी इस तथ्य के बावजूद नियम 5 के तहत वरिष्ठता के लाभ का हकदार था कि उसे आपातकालीन कमीशन अधिकारी या अल्पकालिक सेवा नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में रिहा नहीं किया गया था।

(22) नतीजतन, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हैं, जितने तक रिट याचिका मे अनुमति दी गई थी। हालाँकि, निर्णय उन कारणों पर आधारित है जो विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपनाए गए कारणों से अलग हैं। नतीजतन, याचिका खारिज कर दी जाती है। हालाँकि, हम लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

*जे.एस.टी*

***न्यायमूर्ति के. के. श्रीवास्तव के समक्ष***

**रविंदर सिंह,-याचिकाकर्ता**

***बनाम***

**जनमेजय सिंह और अन्य-उत्तरदाता**

***1997* का ई. पी. सं. 4**

**3 जून, 1999**

*लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-धारा 80,* 81 *और 100-चुनाव याचिका में दलीलें-क्या वे मुकदमे में दलीलों से अलग है-भौतिक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है-निर्वाचित उम्मीदवार के खिलाफ भ्रष्ट प्रथाओं के आरोप-याचिका में उन्हें उन कथनों से जोड़ने का कोई दावा नहीं है-चुनाव याचिका की पोषणीयता।*

*अभिनिर्धारित* किया कि वाद में अभिवचनों से संबंधित कानून चुनाव याचिका में किए गए अभिकथनों से संबंधित कानून से पूरी तरह से अलग है। इन मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से

*(अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय, वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके, और किसी अन्य उद्देश्य के लिया इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।)*

*रवि अमितोज़, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी*